

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर
तेजसिंह बनाम सरकार
अपील संख्या 41/2019

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 41/2019

तेजसिंह पुत्र नेकसिंह जाति गोला निवासी खेरिया-बिलौच्च तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास।

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 09.04.2019 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी बनाम तेजसिंह मि0न0 08/2018 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956।


उपस्थित :- 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्त
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 06.01.2022

अपीलान्त ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 09.04.2019 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्त को ग्राम खेरिया बिल्लौच की आराजी खसरा नम्बर 594 रकवा 8 वीघा 7 विस्वा में से 0.04 विस्वा पर अतिक्रमी मानकर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

1


अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)


अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत

पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट की स्वयं की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 595 की डौल-मेड खसरा नम्बर 594 से मिलती जुलती है। अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 594 पर कोई रबी की फसल नहीं बोई है। अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 28.03.2019 को तहसीलदार रूपवास को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया था कि अपीलान्ट के खातेदारी के खसरा नम्बर 595 की नाप स्वयं तहसीलदार अपनी उपस्थिति में करावे, यदि अपीलान्ट का कोई कब्जा हो तो उसे व तुरन्त हटा लेगा परन्तु तहसीलदार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपीलान्ट की इस प्रार्थना पत्र पर कोई विचारण किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर बेदखली व पैनल्टी का आदेश पारित कर दिया। उन्होने यह भी जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 594 गैरमुमकिन रास्ता में शुरूआत में कोकसिंह व भगवानसिंह लठैत व्यक्तियों ने पक्का निर्माण कर रखा है, इसे धर्मशाला के नाम से पुकारते हैं जबकि धर्मशाला नाम की कोई स्थिति वहां पर नहीं है। यह लोग इसे निजी काम में लेते हैं, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है और न ही यह सार्वजनिक हित के काम आती है। पटवारी हल्का इनका दोस्त है और उनका पटवारी के यहां आना जाना खाना-पीना-सोना है। इस कारण इस धर्मशाला को बचाकर हमारे खसरा नम्बर 595 में 594 का रकवा बढ़ाकर हमारा अतिक्रमण बताया है जो बिल्कुल गलत है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि पटवारी हल्का ने ग्राम की राजनैतिक वैमनस्यता के वशीभूत होकर अपीलान्ट के विरुद्ध अपीलान्ट के विरुद्ध यह झूठी रिपोर्ट पेश की है। क्योकि अपीलान्ट ने कई बार कोकसिंह व भगवानसिंह की इस अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई धर्मशाला की शिकायत की थी इस कारण पटवारी ने अपनी दोस्ती निभाते हुये कोकसिंह व भगवानसिंह के द्वारा अतिक्रमण करके खसरा नम्बर 594

ने अध्याकथित धर्मशाला को बचाने के लिये हमारे विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्का ने अपीलान्त को कई बार धमकी दी है कि खसरा नम्बर 594 में अतिक्रमण करके बनाये गये मकानात के बारे में शिकायत मत कर नहीं तो तेरी खातेदारी की भूमि को तुझसे छीन लूंगा। दिनांक 03.04.2019 को अपीलान्त के अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश किया था उस तहसीलदार ने यह कहा कि हम इसे देख लेंगे और आगामी तारीख पेशी अपीलान्त को नहीं दी गई इसके बाद कई बार तहसील के चक्कर भी लगाये लेकिन कोई संतोषजनक जबाब नहीं मिला। दिनांक 08.05.2019 को पटवारी हल्का ने घर पर आकर धमकी दी कि अपना कब्जा हटा ले क्योंकि तहसीलदार ने बेदखली व पैनल्टी के आदेश दिये है। अपीलान्त उसी दिन तहसील गया व जांच की तो सही पाया, तो तुरंत प्रभाव से उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल तैयार होकर दिनांक 10.05.2019 को प्राप्त हुई तब उसे पढकर असल जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम को प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्त ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2019 के द्वारा अपीलान्त को विवादित आराजी सारा नम्बर 594 वाकै ग्राम खेरिया बिल्लौच रकवा 8 वीघा 17 विस्वा में से 0.04 विस्वा पर तिकमी मानते हुये बेदखली एवं पैनल्टी कायम की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्त ने दिनांक 03.04.2019 को विवादित भूमि की पैमाईश कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है और न ही पत्रावली में पैमाईश के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। उक्त प्रकरण में विधिवत जाँच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार रूपवास को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वे प्रकरण में विधिवत जाँच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सुनाया गया।


(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)